महामहिम राज्यपाल

श्री गुरुमुख निहाल सिंह का अभिभाषण

25 अप्रेल, 1957

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण,

इस विधान सभा के पहले अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप में से बहुत से सज्जन ऐसे हैं जो संसदीय कार्यवाही में निपुण हैं और जिन्होंने राज्य में कानून बनाने और प्रशासन के इतिहास में पूरा योग दिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने विधानिक क्षेत्र में नये सिरे से पदार्पण किया है। उनको मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूँ और संसदीय कार्य में उनके सफल होने की कामना करता हूँ। आप इस क्षेत्र में चाहे अनुभवी हों या नये ही में आये हों, मैं आशा करता हूँ कि आप निरन्तर स्मरण रखेंगे कि जनता ने आप पर भरोसा व विश्वास किया है और आप इस सम्मान के योग्य बनने के लिए निरन्तर परिश्रम करते रहेंगे। आपका प्रत्येक काम, चाहे वह इस सदन के भीतर किया जाय या बाहर, जनता की निगाह में रहेगा और उसकी जाँच लोकसेवा के अति उच्च मापदण्ड से की जायेगी। आपका पद विशेष अधिकारों से उतना युक्त नहीं है जितना कि जनता की सेवा और जनता के प्रति उत्तरदायित्व से सम्बन्धित है।

2. आजाद होने के साथ-साथ दस वर्ष पहले इस देश के लोगों को शीघ्रता से समूचे देश की आर्थिक प्रगति करने की तीव्र अभिलाषा हुई और उस अभिलाषा की पूर्ति के लिये उन्होंने एक अति उपयोगी कार्यप्रणाली, अर्थात् आयोजन का आविष्कार किया। आयोजित विकास में हम अपरिचित थे इसलिए हमने अपना परीक्षण आंतरिक उत्साह से आरंभ किया, किन्तु हमें जल्दी ही विश्वास हो गया कि हम सही रास्ते पर हैं और यदि हमने अपना उत्साह कायम रखा तो अवश्य ही लक्ष्य तक पहुँच जायेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना के परिणाम हमारे अनुमान से बढ़ कर हुए। राष्ट्र ने अन्न की कमी दूर करने में काफी सफलता प्राप्त की, बिजली और सिंचाई की कई बड़ी-बड़ी योजनाओं को पूरा किया, बहुत-सी ऐसी योजनाओं की नींव डाली, कई बुनियादी और भारी उद्योग जिनमें इस्पात के कारखाने शामिल हैं, स्थापित किये, घरेलू उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन दिया और इन सबसे ऊपर उन सामाजिक सेवाओं का वास्तविक प्रारम्भ किया जो जनसाधारण के जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति व शिशु-कल्याण, गाँवों का पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, श्रम-कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में की जाने वाली कार्यवाहियों का एक नया महत्व हो गया और वे उस ग्रामवासी के जीवन का अभिन्न अंग बनेंगे जो उन्हें अब तक दूर से ही, यदि सन्देहपूर्वक नहीं तो लापरवाही से देखता था।

3. दुर्भाग्यवश हमें इस राज्य में कई खास समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके कारण पहली योजना के प्रारम्भिक वर्षों में योजना और विकास के प्रति हमारे प्रयत्नों में कमी रह गई। विभिन्न दर्जे के विकास, दृष्टिकोण परम्पराओं और रीति-रिवाजों वाले 20 से अधिक राज्यों की एकरूप आधुनिक राज्य में संयुक्त करने की समस्या का हमारा अनुभव देश में अन्य राज्यों के ऐसे अनुभव से बिलकुल भिन्न था। इसका परिणाम यह हुआ कि पहली योजना के पाँच वर्षों में से करीब दो या तीन वर्ष के लिए हम प्रशासन के प्रश्नों को सुलझाने में लगे रहे। हमारी सफलता इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आंकी जानी चाहिए, अन्य राज्यों के विषय में काम में लाये गये मापदंडों का राजस्थान के बारे में प्रयोग करना उचित नहीं होगा।

4. किसी राज्य के विकास के लिए पहली आवश्यकता, कानून और व्यवस्था बनाये रखने की है, और इसमें हमने अपूर्व सफलता प्राप्त की है। राज्य के एकीकरण के समय, डाकुओं और उपद्रवी व्यक्तियों ने, जो जनता को निरन्तर लूट रहे थे और भयभीत कर रहे थे, विशाल क्षेत्रों को आक्रान्त कर रखा था। कई सुदूर क्षेत्रों में जान और माल को बहुत खतरा था और शांति व स्थिरता का पर्याप्त अभाव था। सरकार ने इस समस्या का दृढ़तापूर्वक सामना किया। इसके फलस्वरूप आज उन इने-गिने गिरोहों के अतिरिक्त जो कि भय व लूटमार के शर्मनाक नाटक में अपना आखिरी अभिनय कर रहे हैं, सब का सफाया हो चुका है।

5. विकास के क्षेत्र में हमने सामान्यतः पहली योजना में पर्याप्त प्रगति की है। 60.48 करोड़ रुपये की कुल नियत राशि में से करीब 85 प्रतिशत खर्च किया गया। अनाज की पैदावार निस्संदेह बढ़ी है, फिर भी इस दिशा में हम सुरक्षित स्थिति पर पहुंचने से अभी दूर हैं। खेती होने योग्य कुल क्षेत्र के करीब 10 प्रतिशत क्षेत्र में ही अभी तक सिंचाई की जा सकती है। और चूंकि राज्य के अनेक भागों में वर्षा कम और अनिश्चित रूप से होती है, अतः किसानों को बारम्बार अकाल का डर लगा ही रहता है। फिर भी प्रथम योजना में सिंचाई के कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई। भाखड़ा बांध का पानी लाने के लिए राजस्थान में पहली योजना के अन्त तक नहरें करीब करीब तैयार हो गई थीं और 1955-56 की खरीफ की फसल में करीब 40 हजार एकड़ जमीन में सामयिक सिंचाई होने लगी। प्रथम योजना की समाप्ति के समय चम्बल योजना की भी नहरों का काम पूरी रफ्तार पर था। प्रथम योजना की अवधि में अन्य परियोजनाओं द्वारा करीब 5 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हुई। लेकिन बिजली शक्ति की योजनाओं की दिशा में हमारा काम कुछ अधिक संतोषजनक नहीं रहा। बहुमुखी योजनाओं में यद्यपि उचित प्रगति हुई लेकिन भाखड़ा की बिजली वितरित करने के लिए तार की लाइन डालने का काम पूरा नहीं किया जा सका। राज्य में थरमल सप्लाई (बिजली) की संरक्षा तक उसका विस्तार उतना नहीं हुआ जितना कि उम्मीद थी। लेकिन सड़कें बनाने के कार्यक्रम में संतोषजनक प्रगति हुई। करीब 5 करोड़ रुपये के खर्च से लगभग 675 मील लम्बी पक्की सड़कें बनाई गईं और एक हजार मील से अधिक लम्बी मौजूदा सड़कों को सुधारा गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण आदि अन्य क्षेत्रों में भी उचित प्रगति हुई।

6. माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना में करीब 105 करोड़ रुपया का कुल खर्चा करने का प्रावधान है। इसमें से 45.45 करोड़ रुपया सिंचाई और बिजली योजना के कार्यों पर खर्च किया जायेगा। हालांकि मुख्य बहुमुखी परियोजनाओं के लिये 20 करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत पड़ेगी लेकिन हमने 11 करोड़ से अधिक रुपया दूसरी छोटी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये भी रखा है। साथ ही यह भी तय हो चुका है कि राजस्थान नहर परियोजना का काम, जिस पर करीब 66.46 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है और जिससे करीब 34 लाख एकड़ रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी, हाथ में लिया जायेगा और यथासम्भव शीघ्रता से पूरा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत जिन कामों के लिए रकम नियत की गई है उनमें से 5.64 करोड़ रुपये की रकम ग्राम तथा छोटे उद्योगों के लिए है। भेड़ तथा ऊन विकास सम्बन्धी और हाथ करघा उद्योग सम्बन्धी योजनाओं पर, जो कि राज्य के दो खास ग्राम उद्योग हैं, विशेष ध्यान दिया जायेगा। सड़कों के विस्तार और सुधार के लिए करीब 9 करोड़ रुपया रखा गया है। शिक्षा के मामले में यह राज्य कुछ पिछड़ा हुआ है अतः 10.5 करोड़ से अधिक रुपये इस क्षेत्र में खर्च किये जाने के लिये रखे गये हैं। साथ ही कृषि, पशुपालन, मछली पालन तथा वनों की उपेक्षा नहीं की गई है। इन योजनाओं के लिये कुल 12.5 करोड़ से अधिक रुपया नियत किया गया है। यदि यह सारा खर्चा उचित रूप से किया गया तो राज्य की अर्थव्यवस्था अवश्य ही काफी सुधर जायेगी।

7. दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1956-57 में हमने विकास योजनाओं पर कुल खर्च के लिये 19.83 करोड़ रुपया बजट में रखा था। पहले 9 महीनों में वास्तविक रूप से 6.7 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और पिछले तीन महीनों में हुए खर्चे को मिलाकर कुल 13.02 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार हम बजट में रखी गई रकम का करीब 70 प्रतिशत खर्च कर चुके होंगे। इससे ऐसा मालूम हो सकता है कि रुपया कुछ कम खर्च किया गया परन्तु नई योजना के पहले वर्ष में ऐसा होना अनिवार्य था क्योंकि सारी नई योजनाओं की सावधानी से जांच पड़ताल करनी थी, अतः मंजूरी देने में समय लगा। तब भी हम कुछ और काम कर लेते यदि इस वर्ष आम चुनाव न हुए होते, क्योंकि चुनावों के दौरान में करीब 1 महीने तक बहुत से सरकारी अफसरों को चुनाव कार्य में लगे रहना पड़ा। पहले वर्ष की करीब-करीब सारी योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है और उनका काम पूरी रफ्तार पर चल रहा है, अतः दूसरे वर्ष में उचित प्रगति कर दिखाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

8. वर्ष 1957-58 में 20.74 करोड़ रुपया विकास योजनाओं में लगाने का प्रावधान किया गया है। इस रकम का ज्यादा हिस्सा उन योजनाओं को पूरा करने में खर्च किया जायेगा जो कि इस समय पहले से ही चल रही है। इसलिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं कि वर्ष के आरम्भ से ही उचित प्रगति होती रहे। इसके लिये जो उपाय किये गये उनमें से एक यह था कि वित्त विभाग से यह कहा गया कि वह योजनाओं को बजट में शामिल करने के पहले उनकी जाँच पड़ताल

कर ले। योजनाओं की जाँच पड़ताल करने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई थी जिसमें वित्त विभाग, प्लानिंग विभाग और सम्बन्धित शासकीय विभाग के प्रतिनिधि थे। अब शासकीय विभागों को सिर्फ यह काम करना बाकी रह गया है कि वे विशेष कमेटी से स्वीकार किये गये आधार पर मंजूरियां दे दें।

9. साथ ही यह भी कोशिश की जा रही है कि जो काम सामने है उसके अनुरूप शासन को कार्यशील बनाया जाय। शासकीय जाँच समिति अधिकार सौंपने के काम को जल्दी ही पूरा कर देगी। भ्रष्टाचार की समस्या को हल करने के बारे में भी कुछ उपायों पर विचार किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि जब तक भ्रष्टाचार का बीज ही नष्ट न कर दिया जाय, राज्य को, हर क्षेत्र में लगाई गई भारी रकम का पूरा लाभ प्राप्त न हो सकेगा। अभियोगों की पूरी जाँच और जल्दी पैरवी का प्रबन्ध करना जरूरी है जो किया जायेगा। यह भी तजवीज है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चलाये गये विभागीय मामलों को निपटाने के लिए कोई उचित और प्रभावोत्पादक व्यवस्था कायम की जाय। भ्रष्टाचार और बेईमानी के दायरे को कम करने और खर्च की जाने वाली रकम का बेहतर लाभ उठाने के लिए सरकार बहुत जल्द एक केन्द्रीय स्टोर्स परचेज ऑर्गनाइजेशन स्थापित करने का विचार रखती है। समस्त शासकीय कार्य को शीघ्रता निपटाने के लिये सरकार का उचित कदम उठाने का विचार है। जहां मौजूदा कार्यप्रणाली कष्टसाध्य अथवा अनावश्यक तौर पर लम्बी है वहां उसे उचित तरीके पर सरल बनाना होगा। सरकार की यह भी मंशा है कि सब श्रेणियों के अधिकारियों को यथासम्भव अधिक-से-अधिक सीमा तक अधिकार सौंप दिये जायें और काम के निपटाने में उन्हें अपनी जिम्मेदारी अनुभव करने के लिये प्रोत्साहित किया जावे। आशा है कि इन तरीकों से तथा शासन की मशीनरी को कड़ा करने के अन्य तरीके अपना कर राज्य विकास कार्य के दूसरे वर्ष के कार्यक्रम को विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने हाथ में ले सकने में समर्थ होगा।

10. जैसा सदन को मालूम है राज्य में जागीर-पुनर्ग्रहण का काम बिना किसी भारी कठिनाई के आगे बढ़ रहा है। भूमि के सम्बन्ध में हर प्रकार के मध्यवर्गों को मिटा देना सरकार का ध्येय है। इसमें केवल जागीरदारी प्रथा को पूरी तरह से मिटा देना ही नहीं बल्कि जमींदारी प्रथा को मिटाया जाना भी शामिल होगा। जमींदारी प्रथा को मिटा देने के लिए जल्द ही कदम उठाये जायेंगे। सरकार इस बात के लिए भी उत्सुक है कि भूमि पर अधिकतम अधिकार व सुरक्षा वास्तव में खेती करने वाले के लिए सुनिश्चित की जाये। सरकार उस कमेटी की सिफारिशों पर जो कि भूमि-क्षेत्रों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के वास्ते बनाई गई है, शीघ्र ही निर्णय करेगी। राज्य सरकार जागीरदारों को पुनः बसाने की आवश्यकता को अच्छी तरह महसूस करती है। आशा है, उनके सहयोग से यह मसला संतोषप्रद रीति से हल हो जायेगा।

11. शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी योजनायें ही वे योजनायें हैं जिनका कदाचित साधारण व्यक्ति पर अधिक-से-अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति

[illegible] के लिए विशेष कार्यवाही जरूरी है। पिछले वर्ष में 925 प्राइमरी स्कूल, 100 [illegible] तथा 36 हाई स्कूल या हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गये जिनसे राज्य में स्कूलों [illegible] 8000 प्राइमरी, 900 मिडिल और 250 हाई स्कूल या हायर सैकण्डरी स्कूलों से [illegible] गई है। महिलाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने को महारानी [illegible] में पोस्ट ग्रेज्युएट क्लासें और महारानी कॉलेज, बीकानेर, में डिग्री क्लासें खोल [illegible] सैकण्डरी एज्यूकेशन के लिए एक अलग बोर्ड बनाये जाने का प्रस्ताव है। परीक्षाओं [illegible] रद्दोबदल किये जाने का मसला भी सरकार के विचाराधीन है। छात्रों की पढ़ाई [illegible] ठीक अन्दाजा लगाने के लिए तिमाही इम्तिहानों के स्थान पर, सालाना इम्तिहान [illegible] विषय में लगातार पांच बार परीक्षण करने की तजवीज है। इन्जीनियरिंग कॉलेज, [illegible] माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स चालू किया जायेगा। आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर, में [illegible] स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेज्युएट) क्लासें शुरू की गई हैं। चिकित्सा क्षेत्र में गांवों में [illegible] सम्बन्धी सहायता दी जाने पर खास जोर दिया गया है। द्वितीय योजना में इस कार्य [illegible] लाख से अधिक रुपये की योजना रखी गई है। सन 1957-58 में इस कार्य में करीब [illegible] रुपये का खर्चा होगा। जयपुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विकास की ओर [illegible] वर्ष में ध्यान दिया जायेगा।

1[illegible] राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है परन्तु इस सम्बन्ध में यह सम्भावित [illegible] सम्पन्न है। इसके अमूल्य खनिज पदार्थों का अभी तक केवल अपूर्ण रूप से सर्वेक्षण [illegible] सका है और वे बहुत ही अपर्याप्त रूप में काम में लाये गये हैं। यद्यपि राज्य में कोयले [illegible] नहीं है परन्तु पलाना में भूरे कोयले के बड़े भण्डार मौजूद हैं, उनका जब समुचित विकास [illegible] औद्योगीकरण में उनसे बड़ी सहायता मिलेगी। जांच पड़ताल से मालूम हुआ है [illegible] सीसा, जस्ता तथा कच्ची चांदी के बड़े भण्डारों में से एक उदयपुर से दक्षिण-पश्चिम [illegible] पर स्थित है। खेतड़ी के तांबे के भंडार और किन्हीं-किन्हीं जिलों में अच्छे लोहे [illegible] औद्योगिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण है और उनका इस्तेमाल जल्दी-से-जल्दी होना [illegible]। राज्य की कीमती जिप्सम भण्डार का कुछ अंश, जो देश के दूरस्थ भागों में फर्टीलाइजर [illegible] में काम आता है, राज्य में ही लाभप्रद रूप से काम में लाया जा सकता है। भवन निर्माण [illegible] का उद्योग पहिले से ही खूब विकसित रहा है। मकराने का संगमरमर तथा भरतपुर, [illegible] अन्य स्थानों का बालुआ-पत्थर की मांग उत्तरी भारत के सब बाजारों में पहले से ही [illegible] आधुनिक तरीकों द्वारा इन उद्योगों को भी बहुत लाभ पहुंचाया जा सकता है। उपलब्ध [illegible] के अंतर्गत राज्य सरकार औद्योगीकरण के विकास के लिए अपनी भरपूर कोशिश करता [illegible] है। भाखरा, चम्बल तथा अन्य परियोजनाओं से निकट भविष्य में प्राप्त होने वाली बिजली [illegible] राज्य विशाल पैमाने पर औद्योगीकरण के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र तथा अवसर प्रदान [illegible] है। छोटे-बड़े नये उद्योगों को चालू करने में समस्त समुचित सुविधाएं तथा सहायता प्रदान [illegible] की राज्य सरकार की इच्छा रहेगी।

13. ऊँचे दर्जे की तथा अधिक मात्रा में खादी पैदा करने में राज्य विख्यात है। पिछले एक दो सालों में खादी का उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ा है। हाथकर्घा उद्योग, जो कि राज्य में सबसे अधिक फैला हुआ कुटीर-उद्योग है, 70 हजार बुनकरों को रोजी देता है। भेड़ और ऊन उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है और राज्य में पैदा होने वाली ऊन की किस्म तथा तादाद को सुधारने के लिए विकास की कई योजनाएँ ध्यान में हैं। अपनी दस्तकारी के लिए राजस्थान बहुत पहले से ही विख्यात रहा है। समुचित प्रगति को बनाये रखने के लिए जयपुर की महारानी की अध्यक्षता में दस्तकारी बोर्ड की स्थापना की गई है। इन समस्त प्रवृत्तियों का उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा स्थापित अलग अलग बोर्डों पर होगा। राज्य सरकार इन क्षेत्रों की ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहती है ताकि केन्द्रीय बोर्डों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उठाने में वे समर्थ हो सकें।

14. राज्य में बड़े पैमाने पर पंचायतों की स्थापना से, ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित प्रवृत्तियों का काफी अंश में विकेन्द्रीकरण हो सका है। सरकार इस बात के लिये इच्छुक है कि स्थानीय निकायों को, विशेष रूप से पंचायतों को, पर्याप्त अधिकार दे दिये जायें और उन्हें काफी जिम्मेदारी सौंप दी जाय ताकि ग्रामीण व सामुदायिक विकास के क्षेत्र में वे एक जबर्दस्त ताकत बन सकें। सरकार की यह इच्छा है कि स्थानीय निकायों तथा आम जनता का सहयोग विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में अभी की अपेक्षा और अधिक लिया जाय।

15. मजदूर और मालिक के बीच सम्बन्ध सन्तोषजनक रहे हैं। कई केन्द्रों में सरकार ने एम्प्लोइज स्टेट इन्शोरेंस स्कीम चालू कर दी है। प्रथम योजना के काल में 11 श्रम कल्याण केन्द्र खोले गये थे और कई अनेक खोलने का प्रावधान है ताकि राजस्थान में 500 या अधिक मजदूरों वाले प्रत्येक औद्योगिक स्थान में केन्द्र हो सके। टैक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, सरकार उसकी सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही करेगी।

16. पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए पहली योजना में 103 लाख रुपये खर्च किये गये। दूसरी योजना में इस कार्य के लिये 228 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। पहली योजना में परिगणित क्षेत्रों तथा जातियों के कल्याण के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया था जिसमें प्राथमिक पाठशालाओं, प्रौढ़ रात्रिकालीन शालाओं, छात्रावासों, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों का खोलना, भूमिविहीन भील कुटुम्बों को फिर से बसाना, सिंचाई के कुओं तथा छोटे पैमाने पर सिंचाई के लिये तालाबों का निर्माण तथा अस्पताल खोलना भी शामिल है। दूसरी योजना में यह कार्यक्रम और भी अधिक प्रगतिशील कर दिया जायेगा। 150 भील कुटुम्बों को पुनः बसाने के लिये उदयपुर डिवीजन में पाँच आदर्श गाँव स्थापित करने की एक योजना बनाई गई है। परिगणित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये भी विशेष योजनायें थीं जिन्हें जारी रखा जायेगा तथा पर्याप्त रूप से विस्तृत किया जायेगा।

17. खाद्य स्थिति सरकार के लिये चिन्ता का कारण बनी हुई है। बेमौसम वर्षा होने के कारण खरीफ की फसल काफी मात्रा में खराब हुई। रबी की फसल को भी ओलों के कारण और [illegible] से पर्याप्त नुकसान पहुँचा है। राज्य सरकार ने सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं लेकिन दुर्भाग्य से सरकार उनमें सदैव पर्याप्त अनाज का स्टॉक रखने में सफल नहीं हो सकी है। राज्य के कुछ हिस्सों में अनाजों की कीमतें काफी ऊँची हैं। इस स्थिति के सम्बन्ध में राज्य सरकार भारत सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है।

18. चूँकि यह विशेषकर बजट-सेशन है, अतः विधान-निर्मात्री कार्यक्रम अधिक नहीं होगा, फिर भी सरकार सदन के सामने, विधान-निर्माण के कई आवश्यक विधेयक जैसे [illegible] बिल, एग्रीकल्चरल डैटर्स रिलीफ बिल, मनी लैण्डर्स बिल तथा पुलिस बिल प्रस्तुत करने का विचार रखती है। इनमें से कुछ सदन द्वारा पारित हो गये थे लेकिन राज्य पुनर्गठन होने के फलस्वरूप व्यपगत हो गये।

19. अब चूँकि चुनावों की धूमधाम समाप्त हो चुकी है, अतः इस सदन तथा सरकार का कर्तव्य है कि वे अपनी सारी शक्तियाँ राष्ट्रीय विकास के कार्य में लगायें, राष्ट्रीय योजना को स्वीकार करके, राज्य सरकारों ने अपने सामने कुछ स्पष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य रखे हैं। समाजवादी समाज व्यवस्था का विकास, जिसमें उत्पादन बहुत अधिक बढ़ेगा, बेरोजगारी काफी मात्रा में कम होगी, आर्थिक दृष्टि से अशक्त लोगों के लिये धीरे-धीरे तरक्की करने के अवसर बढ़ेंगे तथा अमीर और गरीब के बीच की असमानता कम होगी, सभी सरकारों का घोषित उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का निर्माण इसी प्रकार हो सकेगा। इस उद्देश्य के लिये राष्ट्र को कठिन परिश्रम करना है तथा अपना सर्वोत्तम स्वेच्छा से निःसंकोच दे देना है। वर्तमान में कुछ बलिदान किये बिना भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। इस सम्पूर्ण कार्य का वर्तमान पीढ़ी पर अधिक भार है लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जिससे राष्ट्र आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अतीत गौरवपूर्ण रहा है और इसका भविष्य निश्चित रूप से और भी अधिक गौरवमय हो। हममें से प्रत्येक का कर्तव्य है कि जो काम हमें सौंपा गया है उसे भली भांति पूरा करें।

सदन को अपने विचार-विमर्शों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है।

जयहिन्द।